डब्ल्यूटीओ मसौदे से अफ्रीकी देश नाराज

कपास मुद्दे पर व्यापारिक संबंध का समर्थन नहीं कर सकते

नई दिल्ली, 08 मार्च. विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटी) की चौदहवीं मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए कृषि-व्यापार के संबंध में वार्ता समिति के अध्यक्ष की ओर रखे गये संशोधित प्रस्ताव का कपास पर निर्भर चार अफ्रीकी कपास उत्पादक देशों के समूह सी-4 ने विरोध किया.

डब्ल्यूटीओ की सार्वजनिक वेब साइट पर जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सी-4 में शामिल पश्चिम अफ्रीका के चार देशों, माली, चाड, बेनिन और बुर्किना फासो समेत कुछ सदस्य देशों ने कहा है कि वार्ता के इस इस चरण में कृषि व्यापार संबंधी मसौदे का समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कपास का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस मसौदे से उनकी चिंताओं का पर्याप्त समाधान नहीं होता। डब्ल्यूटीओ में कृषि वार्ता समिति के अध्यक्ष और जिनेवा में पाकिस्तान के राजदूत अली सर्फराज हुसैन ने आगामी मंत्रिस्तरीय बैठक यह मसौदा प्रस्तुत किया है। यह बैठक 26 से 29 मार्च तक मैमरून की राजधानी यउंदे में आयोजित की जा रही है। डब्ल्यूटीओ की वेबसाइट पर प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया है कि छह मार्च को हुई कृषि वार्ता समिति की बैठक में अधिकतर सदस्य देशों ने अध्यक्ष की ओर से प्रस्तुत मसौदे का स्वागत किया और इसे सहमति बनाने के लिए एक आधार माना, हालांकि कुछ सदस्य देशों ने कहा कि वर्तमान स्वरूप में यह उन्हें स्वीकार्य नहीं है। श्री हुसैन ने संशोधित मसौदे के बारे में कहा, मेरे विचार में यह पाठ संतुलन बनाने का प्रयास करता है और सदस्यों की उस साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, जिसके तहत वे एक न्यायसंगत और बाजार-उन्मुख कृषि व्यापार प्रणाली की दिशा में काम करना चाहते हैं, जो खाद्य सुरक्षा में सुधार सहित ठोस परिणाम दे सके। उन्होंने कहा कि इस मसौदे के आधार पर मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद जिनेवा लौटने पर वार्ताओं को अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की बेहतर स्थिति में रखेगा.

> कई सदस्यों ने कहा कि भले ही यह उनके सभी दृष्टिकोणों को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करता, फिर भी यह विभिन्न प्रतिस्पर्धी हितों के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाता है और मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में सहमति बनाने के लिए एक अच्छा आधार प्रदान करता है। कुछ देशों ने कहा कि वे चाहते थे कि उनकी विशिष्ट वार्ता प्राथमिकताएं मसौदे में शामिल हों, लेकिन समझौते की भावना से वे अध्यक्ष द्वारा तैयार किए गए प्रारूप को स्वीकार कर सकते हैं। कुछ सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि पाठ में आगे संशोधन किया जाना चाहिए.

गोदरेज का नया मल्टी-क्रॉप कीटनाशक टकाई लॉन्च

सोयाबीन और सब्जी फसलों के कीटों पर भी असरदार

आईएसके जापान के विकसित साइक्लेप्रिन तकनीक से संचालित

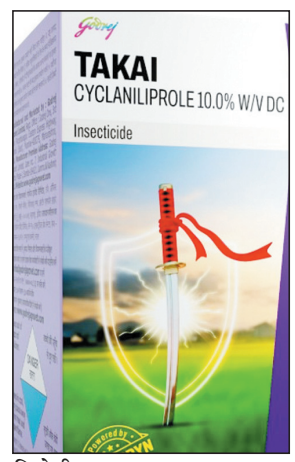

कोलकाता, 08 मार्च. भारत की अग्रणी विविधीकृत एग्री-बिजनेस कंपनियों में से एक, गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड ने नया मल्टी-क्रॉप कीटनाशक टकाई लॉन्च किया है.

आईएसके जापान द्वारा विकसित साइक्लेप्रिनइ तकनीक से संचालित ताकाई, प्रमुख लेपिडोप्टेरन कीटों (इल्ली/सुंडी वर्ग के कीट) के विरुद्ध तेज नियंत्रण और लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है, जो फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। इससे किसानों को फसल की समग्र सेहत बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

कंपनी को धान, मक्का, चना और सोयाबीन के लिए लेबल अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, जबकि पत्ता गोभी और मिर्च फसलों के लिए लेबल विस्तार की मंजूरी की प्रक्रिया जारी है। पश्चिम बंगाल—जिसे व्यापक रूप से भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है और जहाँ प्रतिवर्ष लगभग 15 मिलियन टन धान का उत्पादन होता है—में लेपिडोप्टेरन कीट कृषि उत्पादकता और किसानों की आय के लिए एक गंभीर चुनौती बने हुए हैं।

धान की फसल में येलो स्टेम बोरर (तना छेदक) और लीफ फोल्डर के प्रकोप के दौरान गंभीर परिस्थितियों में 20-40प्रतिशत तक उत्पादन हानि हो सकती है। वहीं, मक्का में फॉल आर्मीवर्म 25प्रतिशत 30प्रतिशत तक नुकसान पहुँचा सकता है, जो अत्यधिक प्रकोप की स्थिति में 60प्रतिशत-65प्रतिशत तक बढ़ सकता है। सोयाबीन में स्पोडोप्टेरा लिटुरा और सेमीलूपर के कारण 20प्रतिशत 30प्रतिशत तक पैदावार घट जाती है, जबकि मिर्च और पत्ता गोभी जैसी सब्जी फसलें भी इसी प्रकार के कीट हमलों से 15प्रतिशत-30प्रतिशत तक प्रभावित होती हैं.

> गोदरेज एग्रोवेट के क्रॉप प्रोटेक्शन बिज़नेस के सीईओ एन.के. राजवेलु ने कहा, प्रभावी कीट प्रबंधन भारतीय किसानों की सफलता को निर्धारित करता है। टकाई के माध्यम से हम किसानों को ऐसा समाधान देना चाहते हैं जो तेज़ी से कीटों की खुराक लेना बंद कराए और लंबे समय तक नियंत्रण बनाए रखे। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, जहाँ धान और अन्य प्रमुख फसलें विभिन्न मौसमों में उगाई जाती हैं और कीट प्रकोप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील रहती हैं, वहाँ समय पर हस्तक्षेप और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यह दृष्टिकोण किसानों को लागत का बेहतर प्रबंधन करने और अधिक स्थिर तथा उच्च गुणवत्ता वाली पैदावार सुनिश्चित करने में मदद करता है.

8वें वेतन आयोग से मिलेगी बड़ी राहत!

54 हजार तक हो सकती है बेसिक सैलरी

नई दिल्ली, 08 मार्च. केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी उम्मीदें बन रही हैं। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने न्यूनतम वेतन में भारी बढ़ोतरी की मांग रखी है.

प्रस्ताव के मुताबिक अगर फिटमेंट फैक्टर 3.0 या उससे अधिक तय किया जाता है तो वर्तमान में 18,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर लगभग 54,000 रुपये तक पहुंच सकती है। यही वजह है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन्स ने जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के स्टाफ साइड को ज्ञापन भेजकर वेतन ढांचे में बदलाव की मांग की है. संगठन का कहना है कि महंगाई, बढ़ते चिकित्सा खर्च और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए अब वेतन का नया ढांचा जरूरी हो गया है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि आज के समय में मोबाइल, इंटरनेट और जैसे खर्च भी जीवन की बुनियादी जरूरत बन चुके हैं, इसलिए इन्हें भी वेतन गणना में शामिल किया जाना चाहिए।

यदि इन सभी खर्चों को ध्यान में रखा जाए तो न्यूनतम वेतन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बनने वाले 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठनों की मांगें तेज हो गई हैं। इसी क्रम में फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन्स ने नेशनल काउंसिल, जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म ङ्क स्टाफ साइड को एक विस्तृत ज्ञापन भेजा है। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3.0 से 3.25 के बीच रखा जाए। यदि यह मांग स्वीकार कर ली जाती है तो वर्तमान में 18,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर लगभग 54,000 रुपये तक पहुंच सकती है। दरअसल, वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन तय करने के लिए 1957 की 15वीं इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के मानकों को आधार माना जाता है।

यह मॉडल प्रसिद्ध पोषण विशेषज्ञ डॉ. वॉलेस आयक्रॉयड के वैज्ञानिक पोषण सिद्धांत पर आधारित है। इन मानकों के अनुसार किसी कर्मचारी के परिवार की बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, कपड़े, ईंधन, बिजली, पानी, शिक्षा और अन्य आवश्यक खर्चों को ध्यान में रखकर न्यूनतम वेतन तय किया जाता है.

दिल्ली- एनसीआर के बाजार महंगे, किराए में 14 प्रतिशत तक उछाल

दिल्ली, 08 मार्च. दिल्ली-एनसीआर के प्रमुख रिटेल बाजारों में दुकानों का किराया लगातार बढ़ रहा है। सीमित जगह और बढ़ती मांग के कारण कई प्रमुख बाजारों में किराए में 2 से 14 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रियल एस्टेट सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राजधानी के पॉश बाजार खान मार्केट ने एक बार फिर देश के सबसे महंगे रिटेल बाजार का दर्जा बरकरार रखा है। यहां दुकानों का मासिक किराया 1,700 से 1,800 रुपये प्रति वर्ग फुट तक पहुंच गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुरुग्राम के गैलेरिया मार्केट में किराए में सबसे ज्यादा 14 प्रतिशत की तेजी देखी गई है, जो बढ़ती रिटेल मांग का संकेत है.

कंपनियों ने एसी के 5-15प्रतिशत तक बढ़ाए दाम

गर्मी से पहले महंगे हुए एसी, कंपनियों ने बढ़ाए दाम

कॉपर-एल्युमीनियम महंगे, नए एनर्जी नियमों से लागत बढ़ी

नई दिल्ली, 08 मार्च। देश में गर्मियों के दस्तक देने से पहले ही एयर कंडीशनर खरीदना महंगा हो गया है। प्रमुख कंपनियों ने एसी की कीमतों में 5 से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी है.

डाइकिन, वोल्टास, ब्लू स्टार, एलजी, हायर और मित्सुबिशी जैसी कंपनियों ने बढ़ती लागत का हवाला देते हुए यह फैसला लिया है। कंपनियों का कहना है कि कॉपर और एल्युमीनियम जैसे कच्चे माल के दामों में तेज बढ़ोतरी, रुपये की कमजोरी और माल ढुलाई की लागत बढ़ने से उत्पादन खर्च काफी बढ़ गया है। इसके अलावा 1 जनवरी 2026 से लागू हुए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के नए स्टार रेटिंग नियमों ने भी लागत में इजाफा किया है। हालांकि इन नए नियमों का फायदा ग्राहकों को लंबे समय में बिजली की बचत के रूप में मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि एसी खरीदने का यह समय अभी भी बेहतर हो सकता है क्योंकि बाजार में पुराने स्टॉक उपलब्ध हैं। जैसे-जैसे गर्मी बढ़ेगी और पुराना स्टॉक खत्म होगा, ग्राहकों को नई और महंगी कीमतों पर ही एसी खरीदना पड़ सकता है। भारत में एयर कंडीशनर बाजार में गर्मियों से पहले ही हलचल तेज हो गई है। एसी बनाने वाली प्रमुख कंपनियों ने अपने उत्पादों की कीमतों में 5 से 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की घोषणा की है.

पश्चिम एशिया संकट का दबाव हावी रह सकता है

मुंबई, 08 मार्च. घरेलू शेयर बाजारों में बीते सप्ताह रही बड़ी गिरावट के बाद आने वाले सप्ताह में एक बार फिर पश्चिम एशिया संकट का दबाव हावी रह सकता है।

अमेरिका और इजरायल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई में गत 28 मार्च को ईरान पर किये गये हमले और उसके बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई के कारण पश्चिम एशिया में स्थिति काफी बिगड़ गयी है। कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही है, वैश्विक व्यापार की आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है और अनिश्चितता अपने चरम पर है। यदि सैन्य टकराव कम होने की खबर नहीं आती है तो बाजार और गिर सकता है। पिछले सप्ताह 03 मार्च को होली के अवकाश के कारण शेयर बाजारों में चार दिन ही कारोबार हुआ.

मुकेश-अनंत अंबानी ने की फिनलैंड राष्ट्रपति की मेजबानी

मुंबई 08 मार्च. रिलायंस उद्योग समूह के प्रमुख मुकेश अंबानी और उनके पुत्र अनंत अंबानी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉ. अलेक्जेंडर स्टब की मुंबई में अपने आवास पर मेजबानी की.

रिलायंस की ओर से सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी में कहा गया है कि राष्ट्रपति स्टब ने दोपहर का समय सौहार्दपूर्ण उनके आवास पर बिताया । रिलायंस उद्योग ने कहा है कि वहां मेहमान राष्ट्रपति के समारोह में मित्रता, सार्थक बातचीत और साझा मूल्यों

के माध्यम से संबंधों को मजबूत करने की भावना झलक रही थी। राष्ट्रपति श्री स्टब अपनी भारत यात्रा के पहले चरण में दिल्ली में थे जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आधिकारिक स्तर की बातचीत की थी.

8 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 2,81,582 करोड़

मुंबई, 08 मार्च. शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह रही बड़ी गिरावट के बीच बीएसई की शीर्ष 10 में से शामिल आठ कंपनियों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण (एमकैप) 2,81,582 करोड़ रुपये घट गया जबकि अन्य दो का 18,209 करोड़ रुपये बढ़ा.

सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक को बाजार पूंजीकरण में सबसे अधिक 53,953 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक को 46,937 करोड़ रुपये और एचडीएफसी बैंक को 46,552 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। अभियांत्रिकी एवं विनिर्माण क्षेत्र की कंपनी एलएंडटी का एमकैप 45,629 करोड़ रुपये कम हुआ। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी बजाज फाइनेंस का एमकैप 28,935 करोड़ रुपये और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टीसीएस का 28,492 करोड़ रुपये घट गया। एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनीलिवर का एमकैप 26,351 करोड़ रुपये और भारती एयरटेल का 4,732.75 करोड़ रुपये कम हुआ.

चावल, गेहूं, चीनी नरम, खाद्य तेलों, दालों में घट-बढ़

नई दिल्ली, 08 मार्च. घरेलू थोक जिंस बाजारों में बीते सप्ताह चावल के औसत भाव गिर गये। चावल के साथ गेहूं और चीनी में भी नरमी रही। खाद्य तेलों और दालों में उतार-चढ़ाव का रुख रहा। सप्ताह के दौरान चावल की औसत कीमत 20 रुपये घटकर सप्ताहांत पर 3,833 रुपये प्रति क्विंटल रह गयी। गेहूं 15 रुपये सस्ता होकर 2,819 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। आटे की कीमत 3,310 रुपये प्रति पर लगभग स्थिर रही। दालों की कीमत में घट-बढ़ रही। मूंग दाल की औसत कीमत 50 रुपये प्रति क्विंटल टूट गयी.

चार दिन में पूंजी बाजार से निकाले 21,013 करोड़

मुंबई, 08 मार्च. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने मार्च के पहले सप्ताह में चार दिन में भारतीय पूंजी बाजार में 21,013 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की.

शुद्ध निवेश लगायी गयी पूंजी और निकाली गयी पूंजी का अंतर होता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, एफपीआई ने इक्विटी में 21,000 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की। हाइब्रिड उपकरणों में उन्होंने 463 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की। म्यूचुअल फंड से भी उन्होंने 345 करोड़ रुपये निकाले। दूसरी तरफ, एफपीआई ने डेट में अपना निवेश 794 करोड़ रुपये बढ़ाया। पश्चिम एशिया में गत 28 फरवरी से जारी संकट के कारण निवेशकों ने पूंजी बाजार से पैसे निकाले.

समाचार विशेष

टिकट न मिलने पर छलका आनंद शर्मा का दर्द

मैं यह मामला हाईकमान के पास नहीं ले जाऊंगा

शिमला. हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अनुराग शर्मा को टिकट दिया है. अनुराग शर्मा कांगड़ा जिला प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष हैं. पार्टी के सीनियर नेता आनंद शर्मा को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है. इस पर उनका दर्द छलक गया है.

उन्होंने कहा कि राजनीति में सेल्फ-रिस्पेक्ट बहुत महंगी पड़ती है. सच बोलना अक्सर जुर्म माना जाता है. आनंद शर्मा को सच बोलने से कभी नहीं रोका जा सकता.

कांग्रेस के फैसले पर आनंद शर्मा ने कहा, मैं निराशा तो नहीं कहूंगा लेकिन एक बात कहूंगा कि स्वाभिमान राजनीति में बहुत महंगा होता है. उसकी कीमत चुकानी पड़ती है. सच बोलना अपराध और अभिशाप समझा जाता है.

मैं हाईकमान से बात नहीं करूंगा- कांग्रेस नेता ने आगे कहा, दशकों से राज्य और देश को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए गर्व की बात रही है. मैं हमेशा हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ रहूंगा. मैं यह मामला हाईकमान के पास नहीं ले जाऊंगा. मैं उनसे बात नहीं करूंगा. बता दें कि कांग्रेस ने सभी को चौंकाते हुए अनुराग शर्मा को उम्मीदवार बनाया. पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, पार्टी की राज्य इकाई की पूर्व अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को राज्य से राज्यसभा सदस्य बनने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था. हालांकि, अनुराग शर्मा की उम्मीदवारी ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दोनों दलों के नेताओं को हैरानी में डाल दिया है.

> **सुक्खू के करीबी माने जाते हैं अनुराग**
>
> अनुराग शर्मा को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बहुत करीबी माना जाता है और कांग्रेस आला कमान द्वारा उनका चयन कांगड़ा जिले के लिए संतुलन साधने वाले कदम के रूप में देखा जा सकता है, जहां पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 15 में से 10 सीट जीती थीं लेकिन उसे केवल दो मंत्री पद मिले थे.

अगले साल के चुनावों में केजरीवाल की भूमिका

नई दिल्ली. अगले साल दो चरण में सात राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं.

पहले चरण में फरवरी और मार्च में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव हैं और उसके बाद साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे. इन सात राज्यों में अरविंद केजरीवाल की बड़ी भूमिका होने वाली है. तभी कांग्रेस का चिंतित होना अनायास नहीं है. दिल्ली की विशेष अदालत से शराब नीति घोटाले का केस खारिज किए जाने और केजरीवाल को जमानत दिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी को संजीवनी मिली है.

एक बार फिर केजरीवाल और आप के पूरी ताकत से लड़ने और आम लोगों के बीच जगह बनाने का मौका मिला है. इसका पहला असर अगले साल होने वाले चुनावों में दिखेगा. यह भी दिलचस्प है कि अगले साल के सभी चुनावों में केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस को नुकसान कर सकती है.

विजय की एंट्री से बीजेपी-डीएमके में से किसे ज्यादा नुकसान?

चेन्नई. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के समीकरण रोज बदल रहे हैं. चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में समझौतों और गठबंधन का दौर चल रहा है. अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, अगले दो हफ्तों के भीतर टीवीके तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है. विजय की सक्रियता से राज्य की पारंपरिक द्विध्रुवीय राजनीति में नया समीकरण बनता दिख रहा है.

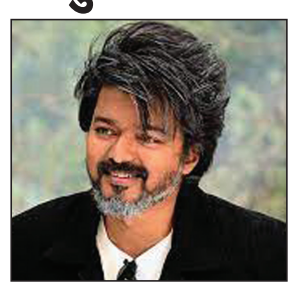

इस बीच सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने चुनाव से पहले अपने गठबंधन को और मजबूत किया है. डीएमके और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी है. समझौते के अनुसार कांग्रेस राज्य में 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसे राज्यसभा की एक सीट भी दी जाएगी. पिछले विधानसभा चुनाव में डीएमके ने 173 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 133 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने गठबंधन में 25 सीटों पर चुनाव लड़कर 18 सीटें जीती थीं. इस बार सीटों की संख्या बढ़ाकर डीएमके सहयोगियों को साथ लेकर चलने का संदेश दे रही है.

इसी दौरान देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम ने भी डीएमके के नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस में शामिल होने का फैसला किया है. उसका यह कदम विपक्षी दलों के लिए झटका माना जा रहा है. माना जाता है कि कुछ क्षेत्रों में इस पार्टी का सीमित लेकिन प्रभावी जनाधार है, जो चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है.

विशेष | प.बंगाल की राजनीति गरमाई

चुनाव से पहले टी पैकेज!

जलपाईगुड़ी . पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर बंगाल का राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाय बागान क्षेत्र एक प्रमुख चुनावी मैदान के रूप में उभर रहा है. ऐसे में केंद्र ने गुरुवार को इस क्षेत्र के लिए संभावित नीतिगत प्रोत्साहन के संकेत दिए हैं. अगर ऐसा हुआ, तो चाय बागान क्षेत्र चुनावी अभियान का एक प्रमुख मुद्दा बन सकता है.

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, जो भाजपा की परिवर्तन यात्रा में भाग लेने के लिए जलपाईगुड़ी में थे, ने कहा कि केंद्र की चाय उद्योग के लिए जल्द ही एक व्यापक पैकेज लाने की योजना है. केंद्रीय मंत्री के ये बयान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दुआर्स और तराई के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर और उनके परिवार उत्तर बंगाल की कई विधानसभा सीटों में निर्णायक वोट बैंक बनाते हैं, जहां भाजपा ने हाल के चुनावों में जीत हासिल की है.

उत्तर बंगाल में चाय उद्योग सबसे बड़ा संगठित क्षेत्र होने के बावजूद, इस क्षेत्र की सबसे पुरानी और सबसे व्यापक बागान अर्थव्यवस्था कई वर्षों से अनियमित मौसम और विभिन्न संरचनात्मक चुनौतियों के कारण दबाव में है. चाय बागान मालिकों और उद्योग संगठनों ने केंद्र सरकार से इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए बार-बार हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है. केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने, भारतीय चाय बोर्ड के अधिकारियों के साथ, गुरुवार को जलपाईगुड़ी स्थित देंगुआ झार चाय बागान का दौरा किया. इस दौरे के दौरान, बागान के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री को चाय प्रसंस्करण इकाई में ले जाकर उत्पादन प्रक्रिया की जानकारी दी. मंत्री को चाय की विभिन्न किस्में दिखाई गईं और गुणवत्ता मानकों और उत्पादन प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण दिया गया.. बाद में उन्होंने बागान की समग्र स्थिति का जायजा लेने के लिए अन्य भागों का भी दौरा किया.

यात्रा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रसाद ने कहा, हम उत्तर बंगाल आए हैं और चाय उद्योग की मौजूदा समस्याओं को सुन रहे हैं. इन समस्याओं के समाधान और श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने के तरीकों पर चर्चा चल रही है.

> **कई विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं बागान मजदूर**
>
> केंद्र सरकार का व्यापक पैकेज का वादा एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समय पर आया है. दुआर्स और तराई क्षेत्रों में चाय बागान मजदूर और उनके परिवार एक बड़ा मतदाता वर्ग बनाते हैं, जो उत्तर बंगाल की कई विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं. विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ, चाय क्षेत्र से संबंधित नीतिगत घोषणाओं का चुनावी महत्व काफी अधिक होने की उम्मीद है. तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा दोनों ही बेहतर वेतन, बेहतर कल्याणकारी योजनाओं और संकटग्रस्त बागानों के पुनरुद्धार के लिए पैकेज का वादा करके चाय बागान मजदूरों का समर्थन हासिल करने पर तुली हुई हैं. उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कोई ठोस वित्तीय और नीतिगत पैकेज लागू होता है, तो यह उत्तर बंगाल के बागान क्षेत्र में चुनावी अभियान का एक प्रमुख मुद्दा बन सकता है, जहां हजारों मजदूरों की आजीविका चाय उद्योग के भाग्य से जुड़ी हुई है.

चुनाव में होगी विजय की परीक्षा

फिल्मों की लोकप्रियता असल चुनावी राजनीति में साकार होती है या नहीं, यह नतीजों के बाद ही पता चलेगा. प्रदेश की राजनीति के दिग्गज चेहरे एमजीआर, करुणानिधि से लेकर जयललिता तक फिल्मों से ही राजनीति में आए. विजय के प्रभाव की बात करें, तो खास तौर पर युवा मतदाताओं, शहरी वर्ग और पहली बार वोट देने वालों के बीच उनका प्रभाव माना जा रहा है. लंबे समय से तमिलनाडु की राजनीति डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द-गिर्द घूमती रही है, लेकिन मौजूदा हालातों में यह मुकाबला त्रिकोणीय बनता दिखाई दे रहा है. - ऐसे में आने वाले चुनाव में विजय की पार्टी वोटों के समीकरण को किस हद तक बदल पाती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं.